## श्रम-वि शाग दिनांक 5 मई, 1986

सं स्रोबिव शिवानी 30-86 15297 - चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं म्युनिसिपल कमेटी भिवानी के श्रीमिक श्री रेड्मल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई ग्रीद्योगिक विवाद है;

श्रीर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपघारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री रेड़मल, पुत्र श्री चन्दगीराम की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

संब्झोब्बिब्बिनी/5-86/15304--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैंब्र राज स्टील इण्डस्ट्रीज, जी.टी. रोड़ उचानी, करनाल, के श्रमिक श्री गंगा राम तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीदींगिक विवाद है.;

ुश्रौर चूंकि हरियाणा के राज्युपाल विवाद को न्यायनिर्णाधे हेतु निर्दिष्ट ृक्ररना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपवारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शिवतयों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44) 84-3-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित अम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री गंगा राम, सपुत्र श्री मानिक यादव की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्न देकर नौकरी छोड़ी है? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किसु राहत का हकदार है?

्रसं० स्रो० वि०/म्रम्बाला/45-86/15310. चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० दी म्रप्पर इण्डिया गलास वर्कस लि०., ट्रेजरी रोड, श्रम्बाला शहर, के श्रमिक श्री रमेंश सिंगल तथा उस के प्रबन्धकों के बीचे इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई श्रीद्योगिक विवाद है;

भौर चू कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिश्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०-3(44)84-3-श्रम दिनांक 18 अप्रेल, 1985 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अन्वाला को विवाद प्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवाद प्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री, रमेश सिंगल, सपुत्र श्री बैनी प्रसाद की सेवाग्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सुं० ओ॰ वि॰/एफ॰डी॰/15316 — चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं॰ विषको ग्राटो मैटल, 2-कें/44 बी. पी. एन. ग्राई. टी., फरीस्वबाद, के श्रमिक श्री राम दुलारे तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलें में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है;

ग्रीर चुंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना मं० 5415-3-अम-68/15254; दिनांक 20 जूनं, 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-अम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गटित अम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायिनर्णर्थ एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिश्य करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अभिकं के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है।

क्या श्री राम दुलारे, पुत्र श्री श्रोखन की सेवाश्रों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं तो, वह किस राहत का हकदार है? जै० पी० रतन,

उप-सचिव, हॅरियाणा सरकार, श्रम विभाग।